आकाषवाणी जयपुर–अजमेर से प्रस्तुत हैं

प्रादेषिक समाचार

दिनांकः 21.01.2026 समय : 18.30 पीएम

- राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय–अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की सम्पतियों और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक लाया जायेगा।
- प्रदेश के किसानों को कल मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किश्त का हस्तांतरण किया जाएगा।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030–31 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
- पीएम–कुसुम योजना में बेहतर काम के लिए–राजस्थान डिस्कॉम्स गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित।

000

राज्य मंत्रिमण्डल ने अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की सम्पतियों और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक लाने, एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण तथा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई नीतियों के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बनने से सार्वजनिक व्यवस्था, सद्भाव एवं मेलजोल से रहने के सामुदायिक चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में दंगे, भीड़ द्वारा हिंसा से अशांति के हालात पैदा होने पर उस क्षेत्र के स्थायी निवासियों को अपनी स्थायी सम्पतियां कम दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इसे रोकने के लिए कानून बनाया जायेगा।

.....

श्री पटेल ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थाई निवासियों की सम्पत्तियों और इन सम्पत्तियों पर किरायेदारों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। इस विधेयक को अब विधानसभा के आगामी सत्र में रखा जाएगा।उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के साथ ही प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के उद्देश्य से राजस्थान एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी का अनुमोदन किया है। एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम के विकास पर केन्द्रित इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स क्षेत्र के विनिर्माण उद्यमों, उपकरण और घटक निर्माताओं से जुड़ी इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा।

.....

कर्नल राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। यह राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग तथा संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश का प्रमुख केन्द्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि किसानों और पशुपालकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

श्री गोदारा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सौर परियोजनाओं के लिए बीकानेर और जैलसमेर में भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में एक साथ मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा।

कैबिनेट के फैसलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि अशांत क्षेत्र घोषित करने संबंधी कानून लाने का राज्य मंत्रिमंडल का फैसला समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ब्यूरोक्रेसी निरंकुश होगी और वहां के नागरिकों के साथ न्याय नहीं हो पायेगा।

000

राज्य विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस सत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने और सकारात्मक चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से चर्चा की गयी। श्री देवनानी ने कहां कि सत्र की तैयारियों को लेकर 27 जनवरी को कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई है।

000

प्रदेश के किसानों के लिए कल मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किश्त का हस्तांतरण किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम सिरोही में आयोजित होगा, जबकि जयपुर का जिला स्तरीय किसान सम्मेलन एचसीएम रीपा में होगा। सम्मेलन के दौरान किसानों को योजना की किश्त लाभ हस्तांतरित करने के साथ ही ग्राम उत्थान शिविरों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

000

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना को 2030–31 तक जारी रखने के साथ ही प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत अब तक आठ करोड़ 66 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह योजना मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह एक हजार से पांच हजार रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है, यह लाभार्थी के योगदान पर निर्भर करती है।

000

लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधायी निकायों को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए प्रयास लिए जा रहे हैं। सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि राज्य विधानसभाओं की वर्ष में कम से कम 30 बैठकें सुनिश्चित की जाएं। श्री बिरला ने बताया कि विधायी कार्यों के मूल्यांकन के लिए एक 'राष्ट्रीय विधाई सूचकांक' तैयार किया जाएगा।

000

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ लेवल अधिकारी, देश में चुनाव आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ हैं। आज नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता को शामिल करते हुए निष्पक्ष मतदाता सूची बनाए रखना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है क्योंकि इसके जरिए सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं। श्री कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में चुनाव प्रबंधन निकायों के संचालन में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।

000

राजस्थान डिस्कॉम्स को पीएम–कुसुम योजना के तहत बेहतर कार्य के लिए गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित ऑल इण्डिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने डिस्कॉम्स की अध्यक्ष आरती डोगरा को यह पुरूस्कार प्रदान किया। प्रदेश में इस योजना के जरिए अब तक एक हजार 307 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इससे एक लाख 41 हजार से अधिक किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली मिल रही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस उपलब्धि पर विभाग के कार्मिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

000

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में समस्याएं सुनीं। सुनवाई के दौरान भरतपुर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता सतीश पांडे ने भी अपनी परिवेदना रखी, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री बेढम ने कहा कि सरकार नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जवाबदेही के साथ काम कर रही है।

000

राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा और मानक पूरे न करने वाले संस्थानों को बंद करने की नीति पर कार्य होगा। आज जयपुर में कुलगुरु समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों को हर साल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी–अध्यापक संवाद शुरू करने और भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रदर्शित करने की पहल पर जोर दिया। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बैठक में बताया कि खाली पदों को भरने के लिए रोस्टर प्रणाली पर काम किया जा रहा है। बैठक में दीक्षांत समारोहों को सादगी से आयोजित करने और गांवों को गोद लेकर विकास कार्य करने के निर्देश भी दिए गए।

000

भरतपुर के एमएसजे खेल मैदान में आज युवा सम्बल मेला आयोजित किया गया। इस मेले में राजस्थान सहित नोएडा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 45 कंपनियों ने भाग लिया। मेले में आठवीं कक्षा से लेकर आईटीआई, बीटेक और उच्च शिक्षा प्राप्त करीब चार हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने साक्षात्कार के बाद पात्र युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपे। संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया और जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने मेले का निरीक्षण कर युवाओं से संवाद किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई।